Statement

Name of the State	Tigers				
	1972	1979	1984	1989	1993
1. Tamil Nadu	033	065	097	095	097
2. Maharashtra	160	174	301	417	276
3. Kerala	060	134	089	045	057
4. West Bengal	073	296	352	353	335
5. Orissa	142	173	202	243	226
6. Karanataka	102	156	202	257	305
7. Bihar	080	110	130	137	137
8. Assam	147	300	376	376	323
9. Rajasthan	074	079	096	099	064
10. Madhya Pradesh	457	529	786	985	912
11. Uttar Pradesh	262	487	698	735	465
12. Andhra Pradesh	035	148	164	235	197
13. Meghalya	032	035	125	034	053
14. Manipur	001	010	006	031	—
15. Tripura	007	006	005	—	—
16. Mizoram	—	065	033	018	028
17. Nagaland	080	102	104	104	083
18. Arunachal Pradesh	069	139	219	135	180
19. Sikkim	—	—	002	004	002
20. Gujrat	008	007	009	009	005
21. Goa Daman & Diu	—	—	—	002	003
22. Haryana	—	—	001	—	—
TOTAL	1827	3015	4005	4334	3750

Pollution of sea water of Indian Coasts

351. PROF. RAM KAPSE: Will the Minister of ENVIRONMENT AND FORESTS be pleased to state:

(a) whether Government are aware of the UNDP Survey Report regarding pollution of sea water of Indian Coasts;

(b) if so, the salient features thereof; and

(c) the action taken/proposed to be taken to combat this pollution?

THE MINISTER OF ENVIRONMENT AND FORESTS (PROF. SAIFUDDIN SOZ): (a) to (c) Information is being collected and will be laid on the Table of the House.

ताज ट्रैपीजियम के लिए योजना

352. **श्री मनोहर कान्त ध्यानी:** क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि आगरा-मथुरा-फिरोजाबाद क्षेत्र के लिये एशियाई विकास बैंक द्वारा प्रायोजित 7000 करोड़ रुपये की लागत वाली एक परियोजना (ताज ट्रैपीजियम) सरकार के पास स्वीकृति के लिये लम्बित पड़ी है;

(ख) क्या यह सच है कि एशियाई विकास बैंक ने इस समझौते पर हस्ताक्षर कर दिए हैं; और

(ग) क्या यह सच है कि इसमें विलम्ब, सरकार और राज्यों के बीच प्रक्रिया संबंधी कार्यवाहियों की जटिलता के कारण हो रहा है, यदि नहीं, तो सरकार आगरा-मथुरा-फिरोजाबाद क्षेत्र के लिये उपरोक्त ताज

ट्रैपीजियम परियोजना को कब तक स्वीकृति देगी और इसे प्रारम्भ करेगी?

पर्यावरण और वन मंत्री (प्रो॰ सैफ-उद्दीन सोज़): (क) से (ग) उत्तर प्रदेश में 6 लाख अमेरिकी डालर की लागत से ताज ट्रैपीजियम के भीतर आगरा-मथुरा-फिरोजाबाद क्षेत्र के पर्यावरणीय सुधार और सतत् विकास के संबंध में एक व्यवहार्यता रिपोर्ट तैयार करने के लिए दी एशियन डेवलप्मेंट बैंक ने भारत सरकार के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय द्वारा टाटा ऐनर्जी रिसर्च इंस्टीट्यूट को यह कार्य सौंपा गया है। टाटा ऐनर्जी रिसर्च इंस्टीट्यूट को यह व्यवहार्यता रिपोर्ट अप्रैल, 1998 तक प्रस्तुत करनी है। व्यवहार्यता रिपोर्ट तैयार करने से संबंधित कार्य प्रगति पर है।

मध्य प्रदेश में बेतवा का प्रदूषण

353. **श्री राघवजी:** क्या **पर्यावरण और वन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि मध्य प्रदेश में बेतवा नदी वर्ष 1997 के दौरान पुनः प्रदूषित हुई थी; यदि हां, तो कितनी बार और प्रदूषण के क्या कारण थे;

(ख) सरकार द्वारा विशेषज्ञ दल की ओर से विगत में प्रस्तुत दो प्रतिवेदनों के संबंध में क्या कार्यवाही की गई है; यदि कोई कार्यवाही नहीं की गई है तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) बेतवा नदी से प्रदूषण समाप्त करने के लिये, जो मंडीदीप, भोपाल, रायसीना और विदिशा में हो रहा है, राष्ट्रीय नदी कार्य योजना के अन्तर्गत 30 सितम्बर, 1997 तक कितनी धनराशि व्यय की गई है और यह धनराशि किन-किन कार्यों पर व्यय की गई है; और

(घ) इस कार्य के लिये कितनी धनराशि उपलब्ध करायी गई है और यह कार्य कब तक पूरा हो जाने की संभावना है?

पर्यावरण और वन मंत्री (प्रो॰ सैफ-उद्दीन सोज़): (क) मध्य प्रदेश में बेतवा नदी अक्टूबर, 1997 में एक अवसर पर पुनः प्रदूषित पाई गई थी। नदी में प्रदूषण की घटना सोम डिस्टिलरीज़ लि॰, सेहतगंज (रायसेन) से औद्योगिक बहिःस्राव के निस्तारण के कारण हुई थी।

(ख) पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड तथा मध्य प्रदेश राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सदस्यों के एक दल द्वारा किए गए निरीक्षण की प्रथम निरीक्षण रिपोर्ट के बाद मंत्रालय एवं मध्य प्रदेश राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा मैसर्स सोम डिस्टिलरीज लि॰ को कारण बताओं नोटिस जारी कर दिया गया था। उद्योग को बहिःस्राव उपचार संयंत्र में आवश्यक क्षमता विस्तार के साथ प्रचालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया था। तथापि, उद्योग ने न्यायालय से स्थगन आदेश प्राप्त कर लिया है तथा केवल बहिःस्राव के भण्डारण के लिए लैगूनों का निर्माण करके प्रचालन जारी रखा हुआ है। मध्य प्रदेश राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा तैयार की गई दूसरी रिपोर्ट के आधार पर मैसर्स सोम डिस्टिलरीज लि॰ को अपने बहिःस्राव उपचार संयंत्र का क्षमता विस्तार करने के लिए एक बार पुनः निर्देश दिया गया था। उद्योग ने इस निर्देश का अनुपालन किया है। तथापि बहिःस्राव उपचार संयंत्र का प्रचालन अभी भी संतोषजनक नहीं है। उद्योग को दिनांक 10.10.97 को बन्द करने का आदेश दिया गया था जिसके खिलाफ उन्होंने मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय में अपील की है।

(ग) राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना के अन्तर्गत विदिशा में प्रदूषण निवारण कार्यों पर 30 सितम्बर, 1997 तक 37 लाख रु॰ की धनराशि व्यय की जा चुकी है। मण्डीदीप एवं भोपाल की स्कीमों पर अब तक कोई व्यय किए जाने की सूचना नहीं है। कार्य की जिन मदों पर धनराशि व्यय की गई है उनका ब्यौरा विवरण में दिया गया है (*नीचे देखिए*)। रायसेन को राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना में शामिल नहीं किया गया है।

(घ) मण्डीदीप, भोपाल और विदिशा में प्रदूषण निवारण कार्यों की अनुमोदित लागत 9.08 करोड़ रु॰ है। इन कार्यों के वर्ष 2001 तक पूरा किए जाने का लक्ष्य रखा गया है।

विवरण

विदिशा में राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना के कार्य की मदें जिन पर व्यय किया गया है

(लाख रुपये)

क्रम सं॰	मदें	धनराशि
1.	अल्प लागत स्वच्छता	28.0
2.	ठोस अपशो प्रबंध	8.0
3.	शवदाहगृह	1.0
	योग:	37.00